भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1910

(06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा प्रदान किया जाना

1910. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन सरकार द्वारा क्रियान्वित 'बीस सूत्री कार्यक्रम' ने ा◌ेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाई है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसके कार्यान्वयन की जिम्मे◌ारी कुछ अन्य संगठनों को भी सौंपी थी;
(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में इसके लिए कृषि विकास शिल्प केंद्र को जिम्मे◌ारी ◌ी गई थी; और
(घ) यि◌ हां, तो क्या सरकार उक्त संगठन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का ◌र्जा ◌ेगी ताकि इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): अपने नागरिकों के लिए कार्यक्रमों के पैकेज जिनमें गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य ◌ ि◌ शामिल हैं, की क्षमताओं में विस्तार करने के सरकार के प्रयास के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) वर्ष 1975 से जारी है। हाल के वर्षों में, ◌ेश में ब◌लते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की तीन बार-वर्ष 1982, वर्ष 1986 और वर्ष 2006 में पुनर्संरचना की गई है। वर्तमान कार्यक्रम जो अब 20 सूत्री कार्यक्रम-2006 (टीपीपी-2006) कहलाता है, अप्रैल, 2007 से जारी है। टीपीपी - 2006 में 20 सूत्र हैं जिनमें ग्रामीण और शहरी लोगों के लाभ के लिए 65 म◌ें शामिल हैं तथा केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा

प्रशासित सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ तालमेल के साथ कार्य करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को टीपीपी की निगरानी की जिम्मे□ारी सौंपी गई है। वर्ष 2017-18 के □ौरान टीपीपी-2006 के तहत की गई प्रगति का ब्यौरा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/QPR%20of%20TPP.pdf. पर उपलब्ध है। विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा रिपोर्ट में उपलब्ध है।

(ख) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मे□ारी कृषि विकास शिल्प केन्द्र सहित किसी संगठन को नहीं सौंपी थी। अंत: इस संस्थान को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का □र्जा □ने का प्रश्न नहीं उठता है।

*****